

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, कोटद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, कोटद्वार के माह 07/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 18.08.2018 से 30.08.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-1

परिचयात्मक: इकाई की विगत लेखा परीक्षा दिनांक 01.8.17 से 14.8.17 की अवधि में श्री रामवीर सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा श्री ए. सी. कटियार वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 07/2016 से 06/2017 तक की अवधि के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2017 से 7/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (अ) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: ग्रामीण निर्माण विभाग के अधीन प्रखंड के परिसीमन में आने वाले समस्त क्षेत्र में ग्रामीण विकास के निर्माण कार्यों का सम्पादित किया जाना।

(ब) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

| वर्ष | प्रा. अवशेष | | आवंटन | | व्यय | | बचत / अभ्यर्पण | |
|------------------------|-------------|-------------|---------|------------|---------|------------|----------------|------------|
| | स्थापना | गैर-स्थापना | स्थापना | गैरस्थापना | स्थापना | गैरस्थापना | स्थापना | गैरस्थापना |
| 2015-16 | 0.00 | 819.11 | 201.22 | 1424.71 | 146.56 | 905.54 | 54.66 | 1338.28 |
| 2016-17 | 0.00 | 1338.28 | 190.08 | 840.73 | 184.00 | 865.46 | 6.08 | 1313.55 |
| 2017-18 | 0.00 | 1313.55 | 214.77 | 433.05 | 210.90 | 744.78 | 3.87 | 1001.82 |
| 2018-19 upto July 2018 | 0.00 | 1001.82 | 233.01 | 36.61 | 76.81 | 201.96 | 156.20 | 836.47 |

ब - (केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत इकाई को प्राप्त धनराशि -शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन सचिव ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई, "ए"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा संलग्न है:

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड कोटद्वारको आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड कोटद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- खण्डित अनुबन्ध की जमानत राशि रु. 5.36 लाखका राजसात नहीं किये जाने तथा त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध के कारण अर्थदण्ड की राशि रु.2.22 लाख अवरुद्ध नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप विभागीय हानि रुपये 7.58 लाख ।

जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जनपद पौड़ी गढ़वाल (ग्राहक विभाग) तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, अव ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- कोटद्वार (निर्माण एजेंसी) के मध्य एक समझौता ज्ञापन दिनांक 21 मार्च 2013 को, राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय रैंस, विकास खण्ड द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु गठित किया गया था जिसमें निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत लागत रुपये 58.82 लाख तथा कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 15 माह विलेखित की गई थी । विलेख के विन्दु संख्या 16(b) के अनुसार निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतुकुल अवधि अथवा कार्य की प्रगति में विलम्ब की स्थिति में निर्माण एजेंसी द्वारा 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती सम्बंधित ठेकेदार से की जानी थी जिसे निर्माण एजेंसी द्वारा ग्राहक विभाग को वापस किया जाना उल्लेखित था ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि, जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जनपद पौड़ी गढ़वाल (ग्राहक विभाग) के पत्रांक- रा.मा.शि.अ./1578-81/ निर्माण कार्य/लेखा/2012-13 दिनांक 28 मार्च 2012 द्वारा रुपये 22675000 की धनराशि चैक संख्या 004966 के माध्यम से कुल 08 निर्माण कार्यों के सम्पादन किये जाने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड कोटद्वार के पक्ष में प्रेषित की गई थी जिसमें राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय रैंस, विकास खण्ड द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु एम.ओ.यू. के अनुसार प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 29.41 लाख सम्मिलित थी ।

भवन निर्माण कार्य का अनुबन्ध संख्या-06/अधी.अभि./2013-14 /दिनांक 22.08.2013 मु.53,61,599 रु.मात्र का मै. यूनाइटेड बिल्डर्स प्रो. श्री शरद गैरोला, जी-131ए राजनगर पालम कालोनी, नई दिल्ली के नाम गठित किया गया था ।

अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 22.08.2013 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 21.08.2014 थी। परन्तु कार्य अनुबंधित तिथि तक पूर्ण नहीं किया गया और रुपये 14,68,013 का भुगतान प्राप्त कर ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया। ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने की स्थिति में अनुबन्ध की शर्तानुसार पूर्ण जमानत धनराशि (5% परफार्मेंस सिक्योरिटी रु. 268080+5% सिक्योरिटी डिपोजिट रु. 268080) कुल रु. 536160 का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ठेकेदार से वसूल किया जाना अपेक्षित था।

ग्राहक विभाग तथा निर्माण एजेंसी के मध्य विलेखित हुए समझौता ज्ञापन के बिन्दु संख्या 16(b) के अनुसार कार्य की प्रगति में विलम्ब की स्थिति में निर्माण एजेंसी द्वारा 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती सम्बंधित ठेकेदार से की जानी थी। तदनुसार विभाग द्वारा निम्न सारणी के अनुसार कटौती की धनराशि सम्बंधित ठेकेदार से वसूल की जानी अपेक्षित थी ।

सारणी-1

| अवधि | एम.ओ.यू.के अनुसार विलम्ब की स्थिति में ठेकेदार से की जाने वाली कटौती | | | | योग |
|--|--|------------|---------|----------|--------|
| | 0.1% | धनराशि | 0.25% | धनराशि | |
| 21.08.14 से 20.11.14 | 5361599 | 5361.599x3 | -- | -- | 16085 |
| 21.11.14 से 22.09.16 | -- | -- | 5361599 | 13404x22 | 294888 |
| विलम्ब की स्थिति में ठेकेदार से की जाने वाली कुल कटौती | | | | | 310973 |

परन्तु ठेकेदार द्वारा अनुबंध खंडित किये जाने के पश्चात् विभाग की उदासीनता एवं लापरवाही के परिणामस्वरूप न तो ठेकेदार पर रु. 536160 का अर्थदण्ड अधिरोपित कर जमानत राशि राजसात की गई और ना ही विलम्ब की स्थिति में रुपये 310973 की कटौती सम्बंधित ठेकेदार से कर **विलेख के बिन्दु संख्या 16(b) के अनुसार** ग्राहक विभाग को प्रेषित की गई की गई।

(ब) आगे यह भी पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु पुनः एक अन्य अनुबन्ध संख्या 24 दिनांक 25.03.2017 को जाहिद अहमद ठेकेदार के साथ रुपये 36,03,153 का किया गया जिसमें कार्य प्रारंभ की तिथि 25.03.2017 एवं पूर्ण करने की तिथि 24.01.2018 थी।

अनुबन्ध स्वीकृति पत्र सं. 1292/ग्रा.नि.वि./अनुबन्ध संख्या-अधि.अभि./मो.मार्ग नि.कार्य/2016-17 दिनांक 25.03.2017 के बिंदु संख्या 7 निर्माण कार्य को **अनुबन्ध में इंगित निर्धारित प्रगति चार्ट के अनुसार प्रगति में लाया जाना अनिवार्य था तथा अन्यथा की स्थिति में जी.पी.डब्ल्यू.9 के क्लॉज-4 की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी।** निर्माण कार्य सम्पादन हेतु प्रगति चार्ट का निर्धारण (प्रथम 2.5 माह में 25% 5 माह में 50%, 7.5 माह में 75% तथा 10 माह में 100%) किया जाना भी त्रुटिपूर्ण था। प्रभावकारी एवं सख्त नियंत्रण हेतु निर्माण कार्य सम्पादन हेतु प्रगति चार्ट का **दिनांक सहित** निर्धारण किया जाना अपेक्षित था।

जबकि विभाग द्वारा निर्धारित प्रगति चार्ट **दिनांक रहित** था परिणामस्वरूप कार्य पूर्ण की तिथि के पश्चात् 6 माह की विलंबित अवधि व्यतीत हो जाने एवं रुपये 2222460 का भुगतान, पुनर्गठित अनुबन्ध पर किये जाने के बावजूद भी कार्य अपूर्ण था। जहाँ कि निर्धारित प्रगति चार्ट के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ **Miles stone पूर्ण नहीं किये जाने पर** अनुबन्ध की राशि का क्रमशः 2.50%, 3.50%, 6% तथा 10% भाग जाहिद अहमद ठेकेदार से अवरुद्ध किया जाना प्रावधानित था। परन्तु कार्य अनुबंधित तिथि तक पूर्ण नहीं किया गया और 6 माह की विलंबित अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद भी 10% भाग अवरुद्ध किये बिना ही रुपये **2222460** का भुगतान जाहिद अहमद ठेकेदार को कर दिया गया। मै. यूनाइटेड बिल्डर्स प्रो. श्री शरद गैरोला से रुपये 536160 तथा जाहिद अहमद ठेकेदार से रुपये **222246** कुल रुपये **758406** की वसूली नहीं की गई।

परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की अपेक्षित पूर्ति नहीं की जा सकी वहीं दूसरी ओर अर्थदण्ड की वसूली, नहीं किये जाने से रु. 758406 की विभाग को हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि मै. यूनाइटेड बिल्डर्स प्रो. श्री शरद गैरोला के अनुबन्ध का अभी तक अन्तिमकरण नहीं हुआ तथा देयक सहायक अभियंता द्वारा भुगतान/अन्तिमकरण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर 10%अर्थदण्ड की वसूली रु.536160 प्रस्तावित है। ग्रामीण निर्माण विभाग परिमंडल पौड़ी के कार्यालय आदेश सं. 780/ ग्रा.नि.वि./अनु.6/अधी.अभि./16-17 दिनांक 08.12.2016 स्वयं का अनुबन्ध होने के कारण खंडित किया गया है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एम.ओ.यू. की शर्त सं. 16(b) का प्राविधान, विभाग द्वारा; अनुबन्ध में नहीं किया गया जिसके कारण सारणी-1 की धनराशि वसूल किये जाने हेतु ठेकेदार बाध्यकारी नहीं था तथा सारणी-2 के अनुसार प्रगति चार्ट का निर्धारण नहीं किया जाना भी त्रुटिपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ Miles stone पूर्ण नहीं किये जाने पर अनुबन्ध की राशि का क्रमशः 2.50%, 3.50%, 6% तथा 10% भाग अनुबन्ध संख्या-06/अधी.अभि./2013-14 /दिनांक 22.08.2013 प्रथम ठेकेदार मै. यूनाइटेड बिल्डर्स प्रो. श्री शरद गैरोला तथा अनुबन्ध संख्या 24 दिनांक 25.03.2017 जाहिद अहमद द्वितीय ठेकेदार का अवरुद्ध नहीं किया गया था। इस प्रकार प्रथम अनुबन्ध में रुपये 536160 तथा द्वितीय अनुबन्ध में रुपये 222246 कुल 758406 की वसूली मै. यूनाइटेड बिल्डर्स प्रो. श्री शरद गैरोला एवं जाहिद अहमद ठेकेदारसे नहीं किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर -2- रु. 546.16 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना ।

(i) खंड की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि विभिन्न ग्राहक विभागों द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागों द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 16 माह से लेकर 84 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्य में से अधिकांश को न सिर्फ अनारम्भ रखा गया था बल्कि जिनमें थोड़ा बहुत कार्य आरंभ भी हुआ था उनको भी इतनी अवधि में भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य में न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे । निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 13 विभागों के 58 कार्यों (संलग्नक -1) की रु.452.25 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 वर्ष से लेकर 07 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी ।

(ii) इसी प्रकार विभाग द्वारा निक्षेप कार्यों के रूप में किए जा रहे कार्यों के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रगति संबंधी रिपोर्ट (जुलाई 2018) का अवलोकन करने पर पाया गया कि 11 विभागों के 21 कार्यों को पूर्ण कर लिया गया था (संलग्नक -2), परंतु लेखा परीक्षा अवधि (जुलाई 2018) तक न तो उन कार्यों को हस्तांतरित किया गया था एवं न ही उन कार्यों की अवशेष धनराशि रु.93.91 लाख को संबन्धित विभागों को वापस किया गया था । इस प्रकार कार्यों के पूर्ण हो जाने के पश्चात भी उक्त धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा गया था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि कुछ विभागों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में देरी करने से एवं कार्यों की पूर्ण धनराशि उपलब्ध न कराने से तथा बार-बार निविदा आमंत्रित किए जाने के वावजूद किसी ठेकेदार के न आने से कार्यों को आरंभ करने/पूर्ण करने में देरी हो रही है। खंड द्वारा कार्यों को शीघ्र आरंभ करने का प्रयास किया जा रहा है, तथा पूर्ण कार्यों की अवशेष धनराशि को शीघ्र ही संबन्धित विभागों को लौटने की कार्यवाही की जा रही है ।

इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संलग्नक -1 के कार्यों हेतु धनराशि विगत 16 माह से लेकर 84 माह तक की अवधि पूर्व प्राप्त हुई थी, इनमें से अधिकांश कार्यों को लेखा परीक्षा अवधि (जुलाई 2018) तक आरंभ ही नहीं किया गया था एवं जिनमें कुछ कार्य किया गया था वे लंबे समय से अपूर्ण पड़े थे एवं उनको पूर्ण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे । इसी प्रकार लेखा परीक्षा अवधि में (संलग्नक -2 के अनुसार) 11 विभागों के 21 निर्माण कार्यों को 01 माह से लेकर 05 वर्ष की अवधि पूर्व ही पूरा किया जा चुका था परंतु इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी इन कार्यों की अवशेष धनराशि को संबन्धित विभागों को वापस न कर अवरुद्ध रखा गया था । इस प्रकार इकाई

द्वारा निक्षेप कार्यो के अंतर्गत कुल रु. 546.16 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

संलग्नक -1

| विभाग का नाम | निर्माण कार्य का नाम | धनराशि प्राप्ति कामाह | 6/2018 तक उपलब्धधनराशि |
|---|--|-----------------------|------------------------|
| पर्यटन विभाग | पर्यटन कार्यालय कोटद्वार के स्टाफ कुवाटर्स | 07/2011 | 306531 |
| | मार्गीय सुविधा वीरोंखाल का निर्माण | 07/2011 | 226457 |
| | मेदनीपुर मंदिर का सौंदर्यकरण | 07/2011 | 390544 |
| | शिव मंदिर कुंडेला का जीर्णोद्धार | 07/2011 | 246000 |
| | ग्रामसभा ग्रसटनगंज मे पार्क निर्माण | 01/2016 | 467801 |
| | नीलकंठ महादेव मे झरने का विकास | 01/2016 | 524320 |
| | ग्राम गेडगढ़ मे मंदिर के समीप निर्माण | 03/2017 | 200000 |
| देवी आपदा | प्रा0 पाठशाला तोल्यूडांड का पुनर्निर्माण | 07/2011 | 328179 |
| | प्रा0 विध्यालय डाबराड का पुनर्निर्माण | 07/2011 | 205215 |
| ग्राम्य विकास | विकासखंड द्वारीखाल कार्यालय भवन का निर्माण | 07/2011 | 1179277 |
| | कार्यालय भवन यमकेशवर का निर्माण | 03/2012 | 322145 |
| | खंड विकास अधिकारी कार्यालय निर्माण वीरों खाल | 11/2013 | 3928913 |
| | विकास खंड दुगगड़ा मे आवासीय भवन | 07/2011 | 302207 |
| | आवासीय भवन नैनीडांडा का निर्माण टाइप -3 | 10/2015 | 587951 |
| | कार्यालय भवन जहरीखाल का निर्माण | 12/2016 | 1000000 |
| | आवासीय भवन टाइप -4 जहरीखाल | 03/2017 | 1200000 |
| | आवासीय भवन टाइप -2 यमकेशवर | 03/2017 | 643520 |
| राजस्व विभाग | राजस्व निरीक्षक चौकी का निर्माण (नैनीडांडा) | 07/2011 | 296365 |
| | राजस्व निरीक्षक चौकी का निर्माण (खिरनी खाल) | 07/2011 | 333384 |
| | ई0 डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोटद्वार | 09/2011 | 196579 |
| शिक्षा विभाग | रा0 इं0 काँ0 जहरीखाल की मरम्मत | 07/2011 | 538592 |
| | रा0 कं0 उच्च0 मा0 विध्यालय कोटरी मे कलाकक्ष | 09/2011 | 222616 |
| | रा0 उच्च0 मा0 विध्यालय वमनगाँव मे कलाकक्ष | 09/2011 | 350798 |
| | रा0 उच्च0 मा0 विध्यालय कुमालडी मे कलाकक्ष | 09/2011 | 258510 |
| | रा0 उच्च0 मा0 विध्यालय जिनेई मे प्रयोगशाला | 09/2011 | 289073 |
| | रा0 उच्च0 मा0 विध्यालयवोडगाँवमेप्रयोगशाला | 09/2011 | 191438 |
| | घनश्याम इंटर कालेज आसनखेत | 09/2011 | 345306 |
| | रा0जू0हा0इं0 कालेज कांडा मुख्यभवन | 03/2012 | 194595 |
| | रा0जू0हा0इं0 कालेज हर्शु मुख्यभवन | 03/2012 | 404041 |
| | रा0उच्च0मा0 विध्यालय भामरईखालवीरोंखाल | 03/2012 | 304193 |
| | रा0 उच्च0 मा0 विध्यालय पड़ेड़ा मे कक्षाकक्ष | 03/2012 | 628976 |
| | रा0 उच्च0 मा0 विध्यालय चोर खिंडा मे कक्षाकक्ष | 03/2012 | 350280 |
| | खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्या 0 निर्माण रिखानिखाल | 02/2013 | 227937 |
| | रा0 उच्च0 मा0 विद्यालय कोटा मुख्य भवन | 04/2013 | 467547 |
| | रा0 उच्च0 मा0 विद्यालयतल्लाबनासमुख्य भवन | 04/2013 | 647522 |
| | रा0 उच्च0 मा0 विद्यालयरौंस मुख्य भवन | 04/2013 | 1776033 |
| रा0 इं0 का0 शकरपुर कक्षाकक्ष का निर्माण | 05/2013 | 818000 | |

| | | | |
|---|--|---------|--------------------|
| | रा0 उच्च0 मा0 विद्यालयपुंडर गाँव जहरिखाल | 05/2014 | 288751 |
| | खण्ड शिक्षा अधिकारीनैनिदांडा | 05/2014 | 370686 |
| | खण्ड शिक्षा अधिकारीजहरीखाल | 05/2014 | 1311592 |
| | खण्ड शिक्षा अधिकारीद्वारीखाल | 05/2014 | 569917 |
| | रा0 उच्च0 मा0 विद्यालयचिलाऊ मुख्य भवन | 06/2014 | 3290068 |
| पुलिस | फायर स्टेशन कोटद्वार का निर्माण | 07/2011 | 2602611 |
| चिकित्सा | रा० एलोपैथिक चि० कांडी के मु० प्रा० भवन | 11/2013 | 1786687 |
| | प्रा० स्वा० केंद्र वडियार गाँव का निर्माण | 08/2016 | 4247242 |
| आयुर्वेदिक | रा० आयु० चि० देवीखेत(द्वारीखाल) | 11/2011 | 439770 |
| | रा० आयु० चि०ठौंड में आवासीय भवन | 09/2013 | 355231 |
| | रा० आयु० चि०शकरपुरका अना० भवन निर्माण नैनिदांडा | 09/2013 | 1369678 |
| पशुपालन | पशु० चिकि० दुगड्डा का निर्माण | 07/2011 | 176204 |
| | पशु चिकि० सतपुली आवासीय भवन टाइप -4 | 05/2015 | 255351 |
| | पशु सेवा केंद्र सार का निर्माण | 11/2013 | 539507 |
| | पशु चिकि० वीरोंखाल में अना० भवन | 04/2013 | 231653 |
| | पशु चिकि० रिखणीखाल में आवा० भवन | 03/2016 | 811316 |
| संस्कृति निदेशालय | कोटद्वार में प्रेक्षाग्रह निर्माण कार्य | 07/2011 | 1591505 |
| उत्तराखण्ड सीमान्त पिछड़ाक्षेत्रविकासनिधि | पशुधन प्रसार केंद्र सल्ट महादेव | 06/2014 | 975000 |
| | फतेहपुर बाजार में सिगाइगधेरे में पुलियानिर्माण | 06/2014 | 278178 |
| खेल | कोटद्वार में स्पोर्ट्स स्टेडियम का चौडीकरण व अन्यकार्य | 07/2016 | 1505210 |
| खाद्यान्न विभाग | राजकीय अन्न भंडार दुगड्डा का मरम्मत कार्य | 09/2016 | 1327781 |
| योग | | | 4,52,24,783 |

(रूपये मे)

संलग्नक -2

(लाख रु. मे)

| विभाग का नाम | कार्य का नाम | आवंटित धनराशि | व्यय धनराशि | अवशेष धनराशि | पूर्ण होने का माह |
|--------------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------------|
| ग्राम्यविकास विभाग | आवासीय भवन टा०-तीन(2-न०)नैनिदांडा | 34.00 | 28.14 | 5.86 | 10/2017 |
| | आवासीय भवन टा०-दो(2-न०)नैनिदांडा | 27.00 | 23.15 | 3.85 | 10/2017 |
| आयुर्वेद विभाग | रा०आयु०चिकि०जोगिमणि का निर्माण (बीरोंखाल) | 36.85 | 24.44 | 12.41 | 09/2016 |
| | रा०आयु०चिकि० शंकरपुर का निर्माण (नैनिदांडा) | 41.85 | 31.20 | 10.65 | 03/2018 |
| | रा० आयु० चिकि० दौंड का निर्माण (बीरोंखाल) | 43.22 | 42.05 | 1.17 | 03/2017 |
| स्वास्थ्य विभाग | प्रा० स्वा० केंद्र कलालघाटी में आवा०/अना० भवन(दुगड्डा) | 219.79 | 215.35 | 4.44 | 12/2016 |
| पशुपालन विभाग | पशुसेवा केंद्र सार यमकेश्वर | 18.87 | 15.10 | 3.77 | 03/2017 |
| | पशुचिकित्सालय रिखणीखाल में आवासीय भवन टाइप -चार(1 न०) का निर्माण कार्य | 29.76 | 23.59 | 6.17 | 03/2018 |
| शिक्षाविभाग | रा० उ० मा० वि० आसौ में विज्ञान प्रयोग शाला नैनिदांडा | 11.48 | 10.91 | 0.57 | 07/2017 |
| | खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नैनिदांडा | 29.15 | 27.09 | 2.06 | 02/2017 |
| | खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारीखाल | 27.99 | 22.10 | 5.89 | 10/2017 |
| | रा०इ०कालेज थल्दा में कक्षा कक्ष (जहरीखाल) | 10.00 | 8.50 | 1.5 | 08/2017 |
| | स्व० घनश्याम इ०का० असंखेत में अनुरक्षण /निर्माण कार्य (जहरीखाल) | 49.49 | 46.44 | 3.05 | 06/2013 |
| | रा०इ०का० जहरीखाल में भवन मरम्मत (जहरीखाल) | 17.03 | 13.01 | 4.02 | 12/2013 |
| रमसा | रा०उ०मा०वि० तल्लाबनास में मुख्य भवन का निर्माण | 51.37 | 48.00 | 3.37 | 03/2016 |
| खेल | राजकीय स्टेडियम कोटद्वार का जीर्णोद्धार एवं अवशेष कार्य | 50.14 | 43.73 | 6.41 | 02/2018 |
| | राजकीय स्टेडियम कोटद्वार का बाड़ सुरक्षा/बेडमिन्टन कोर्ट व अन्य कार्य | 70.95 | 62.38 | 8.57 | 03/2017 |
| सीमांत क्षेत्र | पशु औषधालय भवन का निर्माण दुधार खाल | 12.75 | 10.13 | 2.62 | 02/2018 |
| पंचायती राज | लक्ष्मण झूला कैम्प कार्यालय में मरम्मत कार्य | 6.04 | 5.70 | 0.34 | 07/2018 |
| स्वास्थ्य विभाग | प्रा०स्वा०केंद्र भवन कलालघाटी का निर्माण कार्य दुगड्डा | 219.79 | 217.43 | 2.36 | 06/2016 |
| पर्यटन | ग्राम ग्रास्टन के पार्क निर्माण | 10.00 | 5.17 | 4.83 | 03/2018 |
| योग | | | | 93.91 | |

भाग-दो(ब)**प्रस्तर-03- रु. 7.73 लाख का निष्फल तथा ठेकेदार से रु. 6.94 लाख की लंबित वसूली**

(i) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुंडेरगाँव (जहरीखाल) में 02 कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य किया जाना था। इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग द्वारा रु.10.00 लाख की धनराशि अप्रैल 2014 में इकाई को निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध करा दी गयी थी। धनराशि उपलब्ध कराते समय ग्राहक विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि कार्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाए तथा उसकी देयता आगामी वर्ष के लिए शेष नहीं रखी जाएगी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु ग्राहक विभाग के निर्देशों की अवहेलना कर काफी विलंब से दिनांक 18.03.15 को अनुबंध (03/एड/2014-15) गठित किया गया जिसके अनुसार 17.08.2015 तक निर्माण कार्य पूरा किया जाना था। लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा लिंटर तक ही कार्य किया गया, जिसका भुगतान तृतीय बिल (08.03.2016) के माध्यम से रु.7,73,079/-का किया गया, उसके पश्चात ठेकेदार द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा था एवं उक्त निर्माण कार्य विगत 2.5 वर्षों से बंद पड़ा था। उल्लेखनीय है कि इतनी लंबी अवधि से ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर देने के बाद भी इकाई द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गयी थी। नियमानुसार अनुबंध के साथ संलग्न GPW-9 के क्लॉज 4.5 के अनुसार देरी से कार्य करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए 10% एल डी (अनुबंधित धनराशि की 10% धनराशि अर्थात् रु. 99.04 हजार) अधिरोपित कर उसके तृतीय चालू देयक से वसूल की जानी चाहिये थी साथ ही ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा जाने पर तत्काल अनुबंध का अंतिमिकरण कर ठेकेदार से प्राप्त 5% जमानत प्रतिभूति की धनराशि एवं 5% परफॉर्मंस गारंटी की धनराशि (कुल रु.99.04 हजार) जब्त की जानी चाहिये थी तथा इस कार्य को तत्काल किसी अन्य ठेकेदार से पूर्ण कराया जाना चाहिये था। परंतु विभाग द्वारा कोई समुचित कदम न उठाये जाने से इस कार्य पर किया गया व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ। लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि अनुबंध का अंतिमिकरण करने के लिए ठेकेदार को पत्र लिखा गया है, परंतु वह उपस्थित नहीं हुआ है एवं अनुबंध का अंतिमिकरण कर दूसरे ठेकेदार से कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही शीघ्र ही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा कार्य बंद हो जाने के ढाई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी कोई कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी थी जिस कारण इस कार्य पर किया गया व्यय रु.7.73 लाख का व्यय अलाभकारी साबित हुआ।

(ii) इसी प्रकार राज्य योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल ब्लॉक में कांडाखाल-चेलसैन मोटर मार्ग के बिरमोलीखाल तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था। उक्त मार्ग

निर्माण हेतु शासन द्वारा वर्ष 2014-15 के अंतर्गत 130.17 लाख की धनराशि आवंटित करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कार्य के अंतर्गत प्रथम चरण के कार्य हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग कोटद्वार उत्तराखंड द्वारा रु.96.85 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य के अंतर्गत कुल 1.275 किमी⁰ लंबाई में 5.20 मी. चौड़ाई का पहाड़ कटान का कार्य किया जाना था। उक्त कार्य के प्रथम भाग में पहाड़ कटान के अतिरिक्त Retaining wall, Breast wall, Cross drainage एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के साथ पूरी लंबाई में जी-1 बिछाया जाना था। भाग प्रथम के कार्य करने के लिए कार्य को 02 जॉबों में बांटा गया तथा प्रत्येक जॉब के लिए अधिशासी अभियंता स्तर का अनुबंध किया गया। प्रत्येक अनुबंध के अंतर्गत कार्य 05 फरवरी 2016 को प्रारम्भ कर क्रमशः 04 मई एवं 04 जून 2016 को समाप्त किया जाना था। लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक अनुबंध के अंतर्गत कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा न कर 13 माह से लेकर 15 माह की अवधि के विलंब से पूरा किया गया था। चूंकि समस्त कार्य अनुबंधित अवधि में पूरे न किए जाकर काफी बिलंब से सम्पन्न किए गए अतः अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 sub section 4.5 के अनुसार देर से कार्य पूर्ण करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि (रु 4.96 लाख) एल डी के रूप में अधिरोपित कर उसके देयकों से वसूल की जानी चाहिए थी, परंतु इकाई द्वारा कोई कार्यवाही न कर उक्त ठेकेदारों को अंतिम भुगतान कर दिया गया था। लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि समयवृद्धि का प्रकरण 0.5% अर्थदण्ड सहित मुख्य अभियंता स्तर -1 के यहाँ भेजा गया है जिस पर स्वीकृति आनी बाकी है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समयवृद्धि की अनुमति कार्य करने के दौरान ही प्राप्त की जानी चाहिये थी अब जबकि ठेकेदार को अंतिम भुगतान हो चुका है इस कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। तथा प्रकरण (i) में स्वीकार किया कि अनुबंध का अंतिमिकरण करते समय ठेकेदार की जमानत धनराशि से उक्त धनराशि वसूल की जाएगी। अतः रु.7.73 लाख के अलाभकारी व्यय तथा ठेकेदार से रु 6.94 लाख (1.98+4.96 लाख) की वसूली का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| 100/2014-15 | शून्य | 01,02,03 | - |
| 47/2016-17 | शून्य | 01,02,03,04,05 | - |
| 87/2017-18 | शून्य | 01 | 01 |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| इकाई द्वारा अद्यतन अनुपालन तैयार नहीं किया जाने के कारण प्रस्तर यथावत् रहेगें। | | | | |

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, कोटद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

2. सतत् अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | अवधि |
|---------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1. | ई. हितेश पाल सिंह | अधिशासी अभियन्ता | 12.08.2016 से अब तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, कोटद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जायं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.